भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 194

उत्तर देने की तारीख 01 दिसंबर, 2025

10 अग्रहायण, 1947 (शक)

खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत जलगांव में खेल प्रतिभा की पहचान

194. श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टीओपीएस) या अन्य राष्ट्रीय खेल कार्यक्रमों के अंतर्गत उनकी खेल प्रतिभा की पहचान की गई है या समर्थन प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो एथलीटों, खेल विषयों और प्रदान की गई सहायता की प्रकृति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खेलो इंडिया (केआई) और टीओपीएस जैसी योजनाओं के अंतर्गत जलगांव में खेल अवसंरचना, कोचिंग सुविधाओं और प्रतिभा पहचान को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य या योजना निर्धारित की है;

(घ) यदि हाँ, तो चल रहे या प्रस्तावित अवसंरचना परियोजनाओं और वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है और जलगांव जैसे छोटे जिलों को, खासकर भारत के प्रस्तावित 2036 ओलंपिक लक्ष्यों को देखते हुए राष्ट्रीय हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में शामिल करने के लिए क्या रोडमैप है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख): जी हां। खेलो इंडिया स्कीम के तहत महाराष्ट्र के जलगांव जिले के दो खेलो इंडिया एथलीटों (केआईए) को सहायता दी जा रही है, जिनमें से एक एथलेटिक्स और दूसरे साइक्लिंग के एथलीट हैं। खेलो इंडिया स्कीम के "खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमियां" घटक

के तहत, केआईएएस को मान्यता प्राप्त खेलो इंडिया अकादमियों में शामिल होने का विकल्प दिया जाता है और प्रशिक्षण व्यय, कोचिंग, प्रतियोगिता एक्सपोज़र, शिक्षा, उपकरण सहायता, वैज्ञानिक सहायता आदि के लिए प्रति वर्ष 6.28 लाख रुपये की वित्तीय सहायता [जिसमें 1.20 लाख रुपये आउट ऑफ़ पॉकेट भत्ता (ओपीए) शामिल है] भी दी जाती है।

(ग) से (ङ) इस मंत्रालय की स्कीमें मांग आधारित हैं तथा इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और अन्य पात्र निकायों से प्राप्त प्रस्तावों जो देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक भागीदारी और खेल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के युग्मित उद्देश्य के अनुरूप हो उनपर वित्तीय सहायता के लिए उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के तहत धन की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) के तहत अनुमोदित खेल अवसंरचना परियोजनाओं और उनकी स्वीकृत लागत, जारी की गई धनराशि और उनकी वास्तविक और वित्तीय प्रगति का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.khelo india.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। इसके अलावा, सरकार ने खेलो भारत नीति, 2025 की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य एक समावेशी और मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जहां जमीनी स्तर से ओलंपिक 2036 सहित ओलंपिक पोडियम तक की प्रतिभाओं का विकास हो सके।

*****